

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.20071 of 2025

Rani @ Rani Tiwari

... .. Petitioner/s

Versus

The State of Bihar & Ors.

... .. Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Vikash Kumar Pankaj, Adv.
For the State	:	Mr. P K Shahi, Advocate General
		Mr. P K Verma, AAG-3
		Mr. Sanjay Kumar Ghosarvey, AC to AAG-3

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE

and

HONOURABLE MR. JUSTICE HARISH KUMAR

ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

7 04-05-2026

Mr. Raj Kumar, Secretary, Department of Transport is present virtually.

2. Mr. Dharmendra Kumar Singh, learned Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority is also present in Court.

3. When the matter was taken up on 27.04.2026, we passed the following order, the relevant part of which are as follows:-

“5. At this stage, the learned Advocate General stated that a Cabinet approval is necessary for issuing such notification and fixing the amount payable under settlement or compounding for different sections which deals with different offences. He has assured this Court that he shall do the needful in the meantime and apprise this Court on the next date.”



6. In view of such submission made by the learned Advocate General, list this matter on 04.05.2026 and this Court expects that by the next date, the proposed notification which has been highlighted in our previous order dated 20.04.2026 shall be published and brought on record by way of an affidavit by the Secretary of the Department of Transport, Government of Bihar, Patna.”

4. In terms of such order, supplementary counter affidavit has been filed on behalf of respondent nos. 4 to 6 by one ‘Raghubir Mandal’, Under Secretary, Transport Department, Government of Bihar in which it is stated as follows:-

“5. That it is stated and submitted that in compliance of the Order passed by the Hon'ble High Court the proposed Notification i.e. 'One Time Traffic Challan Settlement Scheme, 2026' for disposal of eligible traffic challan matters in the National Lok Adalat, 2026 has been notified after following the due process and getting approval of Cabinet vide Notification No.3261 dated 30.04.2026. It is also informed that e-gazette has also been published and a copy of the same is brought before this Hon'ble High Court.

6. That it is humbly informed the Hon'ble High Court that to facilitate the disposal of the eligible Traffic Challan matters, particularly through the upcoming next National Lok Adalat several States have passed Notification including the State of Odisha. The State of Bihar has fixed the compoundable/settlement amount as 'One Time Traffic Challan Settlement Scheme,



2026' to facilitate for disposal of Traffic Challan including e-challan, pending in huge number mainly considering the compoundable/settlement amount, fixed by the Govt. of Odisha.

7. That it is humbly submitted that the copy of the Notification has been sent to the Additional Director General of Police (Traffic), Bihar, Learned Member Secretary, Bihar Legal Services Authority, all District Magistrates as well as the concerned Officers of the Department vide Letter no.3280 dated 30.04.2026, requesting therein to take appropriate action and steps by issuing directions for disposal of the pending Traffic Challan. Apart from this all the District Transport Officers (DTOS) have already been directed to support the concerned Officers and District Legal Services Authorities so that Traffic Challan including e-challan matters may be taken up and disposed of in the next National Lok Adalat and huge pendency of e-challan can be reduced accordingly.

8. That it is stated and submitted that with a purpose of mass awareness and publicity of the new notified 'One Time Traffic Challan Settlement Scheme, 2026' is being circulated at wide scale through Letter no.3282 dated 30.04.2026 by publishing in the daily newspapers. In this regard vide Letter No.3281 dated 30.04.2026 a letter has been sent to the Director, I & PRD, requesting therein to publish this 'One Time Traffic Challan Settlement Scheme, 2026' in daily Newspapers for the next three days.


9. That in the facts and circumstances above-mentioned evidently the Respondents have taken several



positive steps including the publication of the Notification namely 'One Time Traffic Challan Settlement Scheme, 2026' after due Cabinet approval for disposal of eligible Traffic Challan matters with wide circulation of the same in compliance of the Orders passed by the Hon'ble Court and for the benefit of public as well."

5. The Gazette Notification dated 30.04.2026 published by the State of Bihar is reproduced in its entirety hereinbelow:-

निबंधन संख्या पी0टी0-40


सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 414) पटना, वृहस्पतिवार 30 अप्रैल 2026

परिवहन विभाग
अधिसूचना
30 अप्रैल 2026

सं० 02/कोर्ट केस-26/2025-3261/परि०—NALSA के दिशा-निर्देशों के अनुसार शमन के रूप में निर्गत ड्र0 चालान से संबंधित लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

उक्त के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा अत्यधिक संख्या में जारी किये गये ऐसे ड्र0 चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं किये गये हैं, जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं या नहीं समर्पित किये गये हैं, इस प्रकार के 31.03.2026 तक के लंबित यातायात ड्र0 चालान के निपटान को सुगम बनाने हेतु बिहार सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा तत्काल प्रभाव से "एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026" की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए प्रभावी होगी।

उल्लंघनकर्ताओं द्वारा ऐसे चालानों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि उक्त योजना में निर्धारित की गयी है।

शमन के रूप में निर्गत चालानों में से ऐसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, इस प्रकार के चालान को सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी, जो नीचे वर्णित अनुसूची के अनुरूप निष्पादित होगी।

अनुसूची

क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि
1	2	3	4
1	177	प्राक्धानों नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन।	500/-



क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध / विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि
1	2	3	4
2	177-क	धारा 118 (चालन विनियम) के अधीन विनियमों का उल्लंघन।	500/-
3	178	पास या टिकट के बिना यात्रा करना।	500/-
4	179	आदेशों, निर्देशों की जानबुझ कर अवज्ञा, बाधा डालना और प्राधिकारी को जानकारी देने से इनकार करना।	मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विहित शास्ति (चालन में उधारविहित) की 50 प्रतिशत राशि
5	180	अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना।	2,500/-
6	181	बीना चालक अनुज्ञापति अथवा निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा याहन का परिचालन करना।	2,500/-
7	182(1)	अशर्ता के पश्चात् यान चलाना।	10,000/-
8	182(2)	परिचालक के रूप में कार्यरत अनर्ह परिचालक या अनुज्ञापति के लिए आवेदन करना या अभिप्राय करना।	10,000/-
9	182क(1)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाय, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000/-
10	182क(3)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाय, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	1,00,000/-
11	182क(4)	मोटरयानों और उनके संघटकों के सन्निर्माण, रख-रखाय, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड	5,000/-
12	182ख	धारा 62क (दोषपूर्ण मोटरयाहन का परिचालन) के उपबंधों का उल्लंघन।	5,000/-
13	183 (1)	अत्यधिक गति से यान चलाना। (i) एल.एम.पी. (ii) एम.एम.पी. / एच.एम.पी	1,000/- 2,000/-
14	186	मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा यान चलाना।	1,000/-
15	189	सार्वजनिक स्थान में दौड़ और गति का मुकाबला	2,500/-
16	192	रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञापन के बिना यान का उपयोग	2,000/-
17	192क	परमिट के बिना यान का उपयोग	10,000/-
18	194क	अधिक यात्रियों का वहन	1,000/-
19	194ख (1)	सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना	500/-
20	194ख (2)	बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अपरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है	500/-



क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध/विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि	
1	2	3	4	
21	194ग	मोटर सार्किल ब्राइपरो और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति	500/-	
22	194घ	सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति	500/-	
23	194ङ	आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता	5,000/-	
24	194च	हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र में हार्न बजाना	1,000/-	
25	196	बीमा न किये गये यान को चलाना	1,000/-	
26	198	यान में अनधिकृत हस्तक्षेप	1,000/-	
27	201	यातायात के मुक्त प्रवाह में अघरोध डालना	500/-	
28	184 (क)	दो पहिया वाहन	1,000/-	परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या-6506 दिनांक 18.08.2023 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन	2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)	3,000/-	
		मध्यम वाहन	4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)	5,000/-	
29	184 (ख)	दो पहिया वाहन	1,000/-	
		तीन पहिया वाहन	2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)	3,000/-	
		मध्यम वाहन	4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)	5,000/-	
30	184 (ग)	वाहन चलाने समय मोबाइल का प्रयोग	5,000/-	
31	184 (घ)	विधि के विरुद्ध किसी रीति में अच्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना।	5,000/-	
32	184 (ङ)	दो पहिया वाहन	1,000/-	
		तीन पहिया वाहन	2,000/-	
		चार पहिया वाहन (छोटा वाहन)	3,000/-	
		मध्यम वाहन	4,000/-	
		भारी वाहन (सभी प्रकार के)	5,000/-	
33	184 (च)	सभी प्रकार के वाहनों के लिए किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना, जो उससे बहुत कम है, जिसकी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जायेगी और जहाँ किसी सक्षम और किसी सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसे रीति में चलाना जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, अभिप्रेत होगा।	5,000/-	



4 बिहार गजट (असाधारण), 30 अप्रैल 2026

क्र० सं०	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन अपराध दंडनीय है।	अपराध / विवरण	शमन के अन्तर्गत देय राशि	
1	2	3	4	
34	190 की उपधारा (2)	दो पहिया वाहन	1,000 /-	परिवहन विभाग के अधिसूचना सं०-10094 दिनांक-02.09.2024 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि
		तीन पहिया वाहन	1,500 /-	
		हल्के मोटरयान (LMV)	2,000 /-	
		मध्यम मोटरयान (MMV)	3,000 /-	
		भारी मोटरयान (HMV)	5,000 /-	
		अन्य वाहन	1,500 /-	

2. सर्वोच्च कोर्ट के क्रियाशील होने तक के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा ई0 चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 414-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

6. The learned Member Secretary, BSLSA, has given the following suggestions for effective disposal of the traffic challan matters in the upcoming National Lok Adalat:-

“1. Cases may be systematically identified and segregated, particularly distinguishing between long-pending challans (beyond 90 days) and recently generated ones, coupled with complete data verification and system readiness to ensure accuracy and real-time accessibility for expeditious disposal.

2. In respect of challans pending for more than 90 days, the Transport Department / concerned authority shall ensure that complete case records (physical and digitally accessible) are transmitted/placed before the concerned courts dealing with such matters prior to the Lok Adalat, so as to



enable effective adjudication and disposal on the day.

3. The system shall reflect the correct status of each challan and enable automatic computation of reduced penalty in accordance with the applicable scheme.

4. Real-time access to the updated database shall be provided to authorised officials to facilitate on-the-spot verification and expeditious disposal of cases.

5. Notices may be issued in a targeted manner to concerned vehicle owners, clearly indicating the challan details, original penalty, reduced amount under the scheme, and the date and venue of the Lok Adalat, so as to ensure informed participation.

6. A multi-mode communication strategy may be adopted, including telephonic outreach and digital messaging platforms such as WhatsApp and SMS, supported by a standardized format to maintain uniformity and clarity in dissemination.

7. Adequate Public awareness and outreach mechanisms may be adopted, including local announcements, display of posters at prominent public locations (petrol pumps, parking areas, DTO offices), and use of social media and digital platforms to maximize public participation in the settlement process.

8. Help and Coordination Desk at Lok Adalat venues may be established, staffed with Para Legal Volunteers, panel advocates, and departmental representatives, to assist litigants in locating cases, understanding the scheme, and facilitating smooth disposal.

9. Proper queue and crowd



management systems may be implemented, including token mechanisms, separate counters for different categories of cases, and installation of display boards for guidance of litigants.

10. The State Transport Department may issue necessary directions to all District Transport Officers (DTOs) for effective implementation of the “Ekmusht Yatayat Challan Niptana Yojna, 2026” in the context of the National Lok Adalat.

11. The A.D.G. (Traffic) may issue appropriate directions of all Superintendents of Police (Traffic) to ensure proper co-ordination, mobilization and smooth disposal of traffic challan matters during the Lok Adalat.”

7. In view of the gazette notification dated 30.04.2026 and due publication, there is likelihood of huge gathering of people in different District Courts to take advantage of the One Time Traffic Challan Settlement Scheme, 2026, floated by the Government for disposal of the traffic challan matters with the reduced amount. In view of the suggestions given by the learned Member Secretary, BSLSA, it is expected that the learned District Magistrates of each of the District shall work in tandem with the Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police and in consultation with the Principal District and Session Judges of the concerned Judgeship, should identify a suitable space proximate to the District Court compound, if



there is insufficient space in the District Court complex, so that it can be ensured that the persons coming to attend the National Lok Adalat, 2026 on 09.05.2026, for settlement of the traffic challan matters, will face no inconvenience, while attending Court which is a corner stone of justice system, rooted in the principle that access to justice is a fundamental right.

8. The arrangement shall also be made, so that the public shall not be asked to deposit the challan amount by cash, but they can avail the online deposit facilities for depositing the amount. The registered vehicle owners, against whom the challans have already been issued, should be informed by the Transport Department within two days, hence, the reduced challan deposit amount, by which their cases can be closed, in the respective mobile phones and/or contact numbers and they shall also be informed about the date and time of the National Lok Adalat and the venue which they shall have to attend for such purpose carrying a valid Id like an Aadhaar Card.

The Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police shall ensure proper security at the place, including placement of CCTV where such matters would be taken up and traffic police should make suitable parking places to handle high footfall, so that orderly settlement can be made. Police and security personnel should be deployed to manage long queues to



prevent disorder. There should be help and co-ordination desk to verify hand copies of documents, including RC, driving licenses, challan notices etc. Since the process is a direct, safe and legal procedure, external agents should not be allowed to interfere with the same.

9. The learned Advocate General submitted that suitable steps shall be taken by the State in publishing the Gazette Notification dated 30.04.2026 relating to traffic challan matters in prominent English as well as Hindi newspapers by 6th of May, 2026; so also on electronic platforms repeatedly. This Court expects that the valuable suggestions given by the learned Member Secretary, BSLSA, shall be adhered to.

10. The matter be placed on **22.06.2026**.

11. On the next date, the complete data of disposal of the traffic challan matters in the National Lok Adalat dated 09.05.2026, the traffic challan amount collected, the steps taken in various aspects for holding the successful National Lok Adalat in respect of the traffic challan matters, shall be brought on record by way of an affidavit by a responsible officer of the Transport Department, Government of Bihar, Patna.

12. A free copy of the order be handed over to the learned Advocate General. The Member Secretary, BSLSA, shall circulate the order to all the Principal and District Sessions



Judges of all the districts of the State of Bihar.

13. Mr. Kumar Saurabh, appearing In-Person submits that he intends to bring some other issues, relating to the traffic challan matters by filing an affidavit.

14. Let the affidavit be filed within a week, by serving a copy of the same to all the learned Counsel for the respective parties.

15. The Court deems it appropriate to place on record its appreciation for the prompt and proactive efforts of the State Government in issuing the requisite Gazette Notification concerning the reduction of traffic challan fees. Such timely intervention reflects a constructive and cooperative approach towards the administration of justice. It is reasonably expected that this measure will significantly facilitate the amicable settlement of pending matters, particularly in Lok Adalats, and thereby contribute to a meaningful reduction in the overall pendency of cases.

(Sangam Kumar Sahoo, CJ)

(Harish Kumar, J)

shivank/-

U			
---	--	--	--

